(राजनाथ सोनकर शास्त्री)

कर्मचारी भी अपने कर्तव्य के प्रति प्रायः उदासी रहते हैं। शिकायतों को या तो सुनते नहीं हैं और सुनते हैं तो उत्तर में मौन ही रहते हैं।

ऐसी स्थित में मैं आपके माध्यम से पुनः संचार मंत्री जी का ध्यान इघर आंक जित करूं गा कि वे टेलीफोन सेवा की ओर अपना ध्यान अवश्य केन्द्रित करें। अधुनिक जिन्दगी की इस महत्व-पूर्ण सेवा को सुचारू रूप से चलाने की दिशा में कदम उठायें। कर्मचारियों, अधिकारियों में जिम्मेदारी की भावना का विकास करें।

MR. DEPUTY SPEAKER: I was in the P&T Department for a long time. Till I was there, it was very efficient.

श्री राजनाय सोनकर ज्ञास्त्री: उपाघ्यक्ष महोदय, नियम 377 में जो मामले प्रस्तुत करते हैं, इनका कुछ भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्या बात है, इस मामले को हमने कई बार हाउस में उठाया है कि नियम 377 में उठाए गए मामलों का प्रापर उत्तर नहीं मिलता है। कोई प्रापर कार्यवाही नहीं होती है। मैं पुन: आपसे निवेदन कहगा कि आप एक बार गवर्नमेंट को कहें।

MR. DEPUTY SPEAKER; The Government will look into it.

SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE: Only the Finance Minister is there.

MR. DEPUTY SPEAKER: He is the Cabinet Minister who is giving money to the Postal Department.

(viii) Crisis in the textile industry and need for Central Governments intervention to restart the closed mills

SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE (Bombay North Central); Textile industry is in the grip of a crisis. There is a spate of closures of textile mills in Ahmedabad, Bombay and number of other places including Delhi

After a year and a half long strike of the textile workers in Bombay, Government announced its decision of taking over 13 mills in Bombay. However not a single mill has started functioning as yet, resulting in the swelling of the ranks of thousands of unemployed workers who have been refused reemployment by the mill owners for participating in the strike.

The major factors responsible for the present predicament are reported to be that, the mill owners have siphoned the profits of the textile industry into other profitable ventures and exploited the workers. On the other hand, inefficiency and rampant malpractices are at the root of failure of the NTC to bring the industry out of crisis.

I would request the Government to nationalise the industry and take urgent steps to restart the mills immediately and save the workers from starvation by re-employing them. At the same time mill owners also should not be allowed to go scotfree.

> (ix) Need to set up some big industries in Carhohiroli (Maharashtra)

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर): उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन निम्न लिखित लोकमहत्व के प्रश्न की और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महाराष्ट्र का विदर्भ कोत्र बहुत पिछड़ा हुआ है और उसमें भी गड़चिरौली जिला, जोकि आदिवासी इलाका है सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है। वहां के लोगों के पास न पहनने को पर्याप्त कपड़ा है और न खाने को अन्न, क्योंकि बहां कोई ठोस रोजगार नहीं है। यह जिला आन्ध्र